

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप सचिव (लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री आवास (न्यू कैण्ट रोड) में मॉड्यूलर किचन एवं जीर्णोद्धार संबंधित सिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य प्रधान सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के पत्र संख्या-51/मुप्र0स0/पी0एस0, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 के माध्यम से परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम देहरादून, इकाई-1 के पत्र संख्या-1132/रानिनि/ देहरादून/2015 दिनांक 22-12-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गए आगणन के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री आवास (न्यू कैण्ट रोड) में सचिव कार्यालय एवं किचन के जीर्णोद्धार एवम् आधुनिकीकरण कार्यों में से मॉड्यूलर कीचन एवं जीर्णोद्धार संबंधित सिविल निर्माण कार्य हेतु टी0ए0सी0/वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 4.26 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार ₹ 13.60 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹ 17.86 लाख (₹ सत्रह लाख छियासी हजार मात्र) के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-568/xxxii(1)/ 01(एक)-01/2016-17 (लेखानुदान), दिनांक 07 अप्रैल, 2016 एवं अलॉटमेंट आईडी-H1604070005, दिनांक 05 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या-1160/xxxii(1)/01(एक)-01/2016-17(मुख्य बजट), दिनांक 05 अगस्त, 2016 एवं अलॉटमेंट आईडी-H1608070373, दिनांक 05 अगस्त, 2016 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गई धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹ 2.86 लाख (₹ दो लाख छियासी हजार मात्र) को व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम देहरादून इकाई-1 प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि ₹ 2.86 लाख (₹ दो लाख छियासी हजार मात्र) का निम्न शर्तों के अधीन नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे:-

(2)

- 1— निर्माण कार्य धनराशि प्राप्त होते ही प्रारम्भ कर, पूर्ण करा लिया जायेगा।
- 2— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 3— कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 4— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
- 5— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जायें तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- 6— विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी।
- 7— स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- 8— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
- 9— आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10— आगणन में प्राविधान/दर/मात्रा/धनराशि तथा विवरण आदि किसी भी प्रकार के अन्तर/पुनरावृत्ति के लिए सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- 11— कार्यदायी संस्था द्वारा मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग से उक्त कार्य का संतोषजनक/संतुष्टिपरक/गुणवत्ता पूर्वक कार्य पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12— कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय के उपरान्त यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 13— आयकर की कटौती संबंधित अनुरक्षण इकाई द्वारा अपने स्तर से करायी जायेगी।
- 14— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/xxxii(1)/2008 दि० 15-12-2008 के अनुसार एम0ओ0यू0 कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. उप सचिव (लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा धनराशि ₹ 2.86 लाख (₹ दो लाख छियासी हजार मात्र) को परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम देहरादून, इकाई-1 के आंध्रा बैंक, शाखा हरिद्वार रोड देहरादून के खाता संख्या-241810100005969, आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या-ANDB0002418, में नियमानुसार जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था का पैन न0-AAACU5701F, टिन न0-05006741040 तथा टैन न0-MRTUO0522E है।

(3)

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 शहरी आवास-800-अन्य भवन-03-राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-118P/XXVII(5)/2016, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या-44 (1)/xxxii(1)/2016/01(तीन)-313/2015(आयोजनागत), तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला।
- 3- मुख्य प्रधान सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
- 5- परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम देहरादून इकाई-1, दून विश्वविद्यालय केदारपुरम्, पो0ओ0 अजबपुर, देहरादून उत्तराखण्ड।
- 6- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग देहरादून को इस निर्देश के साथ कि एन. आई. सी. में अपलोड करायें।
- 7- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग।
- 8- वित्त अनुभाग-5/नियोजन विभाग/बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- निदेशक एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
- ✓ 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

4